आवश्यक धन ?

भारतीय आयोजन / नियोजन के लिए

संसाधन जुटाव → राज्य द्वारा किया जाने वाला नियोजन

Resource-mobilisation for Indian Planning

नियोजन / आयोजन

- लक्ष्य
- रणनीति
- समयावधि
- संसाधन

प्रस्तावना -

भारत में विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केवल बाजार पर्याप्त नहीं है। उपर्युक्त सन्दर्भ में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री पी॰ वी॰ नरसिम्हा राव का निम्न कथन महत्वपूर्ण है कि -

1991

1992 - 1997

'बाजार क्रय-शक्ति आधारित माँग और आपूर्ति में सन्तुलन तो ला सकते हैं लेकिन आवश्यकता और आपूर्ति में नहीं।'

यह ध्यान देने योग्य है कि बाजार कोई सामाजिक/सामूहिक प्रकार के लक्ष्यों के लिए कार्य नहीं करता है और न ही व्यक्तिगत निर्णयों में सामाजिक/सामूहिक प्रभावों को ध्यान में रखता है।

इस प्रकार, भारत में राज्य द्वारा किये जाने वाले नियोजन/आयोजन की आवश्यकता को उजागर किया जा सकता है।

भारत में गरीबी निवारण, समावेशी विकास, मानव-विकास, खाद्य सुरक्षा, विश्व स्तरीय इन्फ्रा, सबके लिए स्वास्थ्य, सबके लिए घर, उत्कृष्ट रक्षा प्रणाली, बेहतर आन्तरिक सुरक्षा आदि लक्ष्यों की

प्राप्ति के लिए राजस्व निवेशन की आवश्यकता है।

भारत में नियोजन की नई संरचना -

भारत में पंच-वर्षीय योजनाओं को हटा दिया गया है।

+

योजना आयोग का अन्त।

+

योजनागत और गैर योजनागत खर्च के वर्गीकरण का अन्त

उपर्युक्त का निहितार्थ यह नहीं है कि भारत

में नियोजन समाप्त हो गया है।

भारत में नियोजन के नये स्वरूप को 2015 से लागू किया गया है। यह पहले की तुलना में अधिक विकेन्द्रित और दीर्घकालिक है।

नीति आयोग की प्रशासनिक परिषद (Governing Council) में राज्यों को भी भागीदारी दी गई है।

प्रशासनिक परिषद् के सदस्यों के रूप में केन्द्र और राज्य Team India की भावना के साथ National Development Agenda को लागू करते हैं। यह सहकारी संघवाद का परिचायक है।

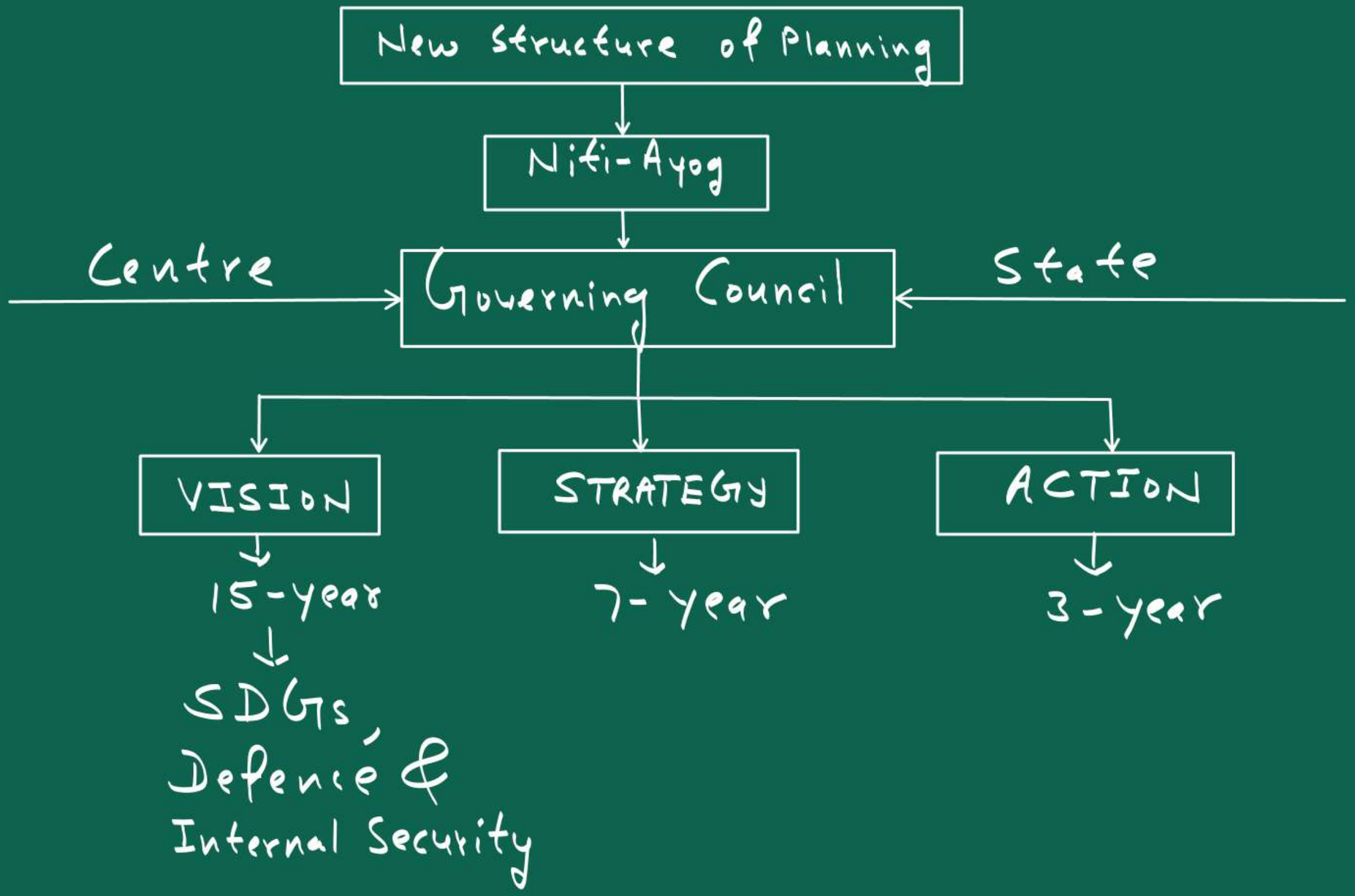
New Structure of Planning
Niti-Ayog
Centre
Governing Council
State
VISION
STRATEGY
ACTION
15-year
7-year
3-year
SDGs,
Defence &
Internal Security

VISION
STRATEGY -
ACTION

संसाधन जुटाव की रणनीति -

1. कर राजस्व से आय को बढ़ाना -

(a) कर की वहनीय दर ।

(b) कृषिगत आय को आय-कर के दायरे में लाया जा सकता है।

↓

विशेष रूप से, ऊँचे कृषकों की ।

(c) नये करों के आरोपण से कर-आधार को बढ़ाया जा सकता है

(d) कर छूटों को कम से कम किया जाये।

(e) कर प्रणाली सरल हो।

(f) कर-प्रशासन में सुधार हो।

(g) Tax Evasion और Tax Avoidance को रोका जाना चाहिये। आदि।

२. सार्वजनिक उद्योगों में।

↓

अधिशेष (Surplus)
या
मुनाफा।

↓

(i) उत्पादन क्षमता का पूरा इस्तेमाल।
(ii) कार्यप्रणाली में सुधार।
(iii) स्वायत्तता (Autonomy) दी जानी चाहिये
(iv) उचित कीमत नीतियों को लागू करना।

3. सार्वजनिक सेवाएं

↓

बिजली, पेयजल, परिवहन, सिंचाई आदि।

↓

पर्याप्त उपभोक्ता शुल्कों की वसूली

User charges

↓

उन पर लगाई गई लागत निकल आये।

4. सरकार के आकार को छोटा किया जाये।

(Downsizing the govt.)

↓

Minimum Govt. & Maximum Governance पर ध्यान दिया जाये।

+

e-governance को बढ़ावा।

+

नये पदों का अधिक सृजन करने के बजाय अतिरिक्त स्टाफ की पुनर्नियुक्ति पर जोर।

5. सरकारी खर्च।

↓

कम

↓

(i) विशेष जोर →
सब्सिडियों को कम करना।
- लक्ष्यानुवर्ती।
- cash transfer को लागू करना।

(ii) नई पेंशन योजना / राष्ट्रीय पेंशन योजना पर जोर।

(iii) ऋण माफी की योजनाओं से बचना। आदि।

इस प्रकार, भारत में निर्वाचन आयोजन के लिए संसाधन जुटाव की एक उपयुक्त रणनीति का निर्माण किया जा सकता है।